राज्यपाल सचिवालय, बिहार

(जन–सम्पर्क शाखा)

राजभवन, पटना–800022

ई–मेल–prrajbhavan@gmail.com
मो॰–9431283596

प्रेस–विज्ञप्ति

राज्यपाल की अध्यक्षता में बिहार की ऐतिहासिक धरोहरों एवं पुरातात्विक महत्त्व के स्थलों के संरक्षण और विकास हेतु बैठक हुई

पटना, 21 जुलाई 2018

आज महामहिम राज्यपाल श्री सत्य पाल मलिक की अध्यक्षता में राज्य की ऐतिहासिक धरोहरों और संरक्षित स्थलों (Protected Sites) के संरक्षण एवं विकास को लेकर एक बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री राघवेन्द्र सिंह, बिहार के विकास आयुक्त श्री शशिशेखर शर्मा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की महानिदेशक श्रीमती उषा शर्मा, राज्यपाल के प्रधान सचिव श्री विवेक कुमार सिंह, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के प्रधान सचिव श्री चैतन्य प्रसाद, भारत सरकार के सिविल विमानन मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री अरूण कुमार, पर्यटन मंत्रालय के महानिदेशक श्री सत्यजीत रंजन, तिरहुत प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त श्री नर्मदेश्वर लाल, ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव श्री विनय कुमार, भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त श्री राजेश कुमार, पथ निर्माण विभाग के विशेष सचिव श्री दिवेश सेहरा, बिहार पर्यटन विकास निगम की प्रबंध निदेशक इनायत खान, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि॰ के एम॰डी॰, सिविल विमानन विभाग, बिहार के निदेशक कैप्टन दीपक कुमार, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के आर्केलॉजिकल श्री अतुल कुमार वर्मा एवं अधीक्षण पुरातात्विक डॉ॰ डी॰एन॰ सिन्हा आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

बैठक को संबोधित करते हुए राज्यपाल श्री मलिक ने कहा कि बिहार की ऐतिहासिक विरासत अत्यन्त समृद्ध है। भारत का 'स्वर्णयुग का इतिहास' वस्तुतः बिहार का ही इतिहास है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मैंने वैशाली और विक्रमशिला का दौरा किया था। उन्होंने बताया कि बिहार की वैशाली, जिसे 'विश्व के प्रथम गणतंत्र' होने का गौरव प्राप्त है, का 'अशोक स्तंभ' वास्तुकला की अद्भुत मिशाल है। उन्होंने कहा कि अभिषेक पुष्करिणी सरोवर, कोल्हुआ की अन्य पुरातात्विक विरासतें, रेलिक स्तूप वैशाली, राजा विशाल का गढ़, चतुर्मुखी महादेव, बनिया पोखर, मिरन जी की दरगाह आदि स्थलों को विकसित किये जाने की जरूरत है। श्री मलिक ने कहा कि वैशाली के 'प्राकृत जैन शास्त्र और अहिंसा शोघ संस्थान' में पुरानी जैन प्राकृत भाषा में रचित कई पांडुलिपियों को संरक्षित किए जाने की जरूरत है। राज्यपाल ने संस्थान में एयर कंडिशनिंग की व्यवस्था को आवश्यक बताया। श्री मलिक ने कहा कि कई जैन सामाजिक संस्थाएँ भी संस्थान के विकास में सहयोग कर सकती हैं। उन्होंने इस संस्थान के विकास हेतु समुचित कदम उठाये जाने की जरूरत पर जोर दिया।

राज्यपाल ने प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के महत्त्व को रेखांकित करते हुए कहा कि तिब्बती पर्यटकों के लिए यह आकर्षण का केन्द्र हो सकता है। राज्यपाल ने भागलपुर हवाई अड्डे के विकास हेतु समुचित कदम उठाये जाने का सुझाव दिया, ताकि अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों का विक्रमशिला पहुँचना संभव हो सके। राज्यपाल ने विक्रमशिला महाविहार के विकास हेतु आवश्यक कदम उठाने हेतु भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधिकारियों को कहा।

लगातार पृष्ठ...2 पर

राज्यपाल ने कहा कि बिहार अपनी ऐतिहासिक धरोहरों और पुरातात्विक महत्त्व के स्थलों को विकसित कर इनकी पर्यटकीय संभावनाओं को व्यापक रूप से बढ़ा सकता है। उन्होंने कहा कि पर्यटन उद्योग के जरिये राज्य को आर्थिक समृद्धि प्राप्त होगी। राज्यपाल ने सुझाव दिया कि सभी ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर लगने वाले साइनेजों पर ऐतिहासिक तथ्यों को वस्तुनिष्ठ एवं रोचक रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा आकर्षक प्रचार–साहित्य भी तैयार होना चाहिए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री राघवेन्द्र सिंह ने कहा कि भारत सरकार 'कल्चरल कॉम्प्लेक्स' या स्टेट म्यूजियम के विकास हेतु आवश्यक वित्तीय सहायता कर सकती है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की महानिदेशक श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि बिहार के पुरातात्विक महत्त्व के स्थलों के उत्खनन हेतु स्वीकृति प्रदान करने में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग पूरी तत्परता दिखायेगा एवं राज्य के Protected Sites (संरक्षित स्थलों) के विकास हेतु हरसंभव सहयोग प्रदान करेगा। श्रीमती शर्मा ने कहा कि ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्त्व के स्थलों के विकास एवं संरक्षण हेतु राज्य को 'समेकित एक्शन प्लान' बनाकर सभी संबंधित विभागों के साथ मिलकर समन्वित चरणबद्ध प्रयास करना चाहिए।

बैठक में बोलते हुए बिहार के विकास आयुक्त श्री शशिशेखर शर्मा ने कहा कि राज्य के संबंधित सभी विभाग ऐतिहासिक धरोहरों एवं पुरातात्विक विकास के स्थलों के समग्र विकास की समन्वित रूपरेखा शीघ्र तैयार कर लेंगे। राज्यपाल के प्रधान सचिव श्री विवेक कुमार सिंह ने कहा कि भारत सरकार एवं बिहार सरकार की अधिकारियों की इस संयुक्त बैठक से निश्चय ही योजनाओं के क्रियान्वयन को गति मिलेगी। बैठक में उपस्थित वैशाली के विधायक श्री राजकिशोर सिंह ने वैशाली के ऐतिहासिक स्थलों के विकास हेतु अपने सुझाव दिये।

बैठक में अधीक्षण पुरातात्विक डॉ॰ डी॰एन॰ सिन्हा ने अपने 'पावर प्रेजेन्टेशन' के माध्यम से वैशाली, कोल्हुआ, रैलिक स्तूप एवं राजा विशाल के गढ़ में उपलब्ध सुविधाओं का उल्लेख किया तथा 'Gap Analysis' के जरिये यह बताया कि इन स्थलों पर और किन–किन आवश्यकताओं को पूरा किया जाना जरूरी है। उन्होंने विक्रमशिला महाविहार, नालन्दा व राजगीर के स्मारक–स्थलों –Cyclopean wall, Sone Bhandar cave, अजातशत्रु का किला, बाणगंगा स्तूप और सासाराम के शेरशाह सूरी के मकबरे, केसरिया स्तूप, नंदागढ़ के स्तूप व अशोक स्तंभ, रामपुरवा तथा अरेराज के Ashokan Pillars, बराबर की गुफा, मनेरशरीफ दरगाह, नागार्जुनी हिल, बकरौर के सुजाता कुटीर तथा चिरान्द (सारण) आदि स्थलों के संरक्षण एवं विकास पर जोर दिया। उन्होंने इन स्थलों पर सड़क–सम्पर्कता विकसित करने, विद्युत की निर्बाध आपूर्ति, पेयजल, शौचादि–सुविधाओं के विकास, कैफेटेरिया के निर्माण कार्यों, पर्यटकीय स्थलों पर वाइ–फाइ सुविधा उपलब्ध कराने, पर्यटकीय होटल एवं कुटीरों के निर्माण आदि की वस्तुस्थिति की जानकारी अपने प्रेजेन्टेशन के जरिये दी।

बैठक में सिविल विमानन मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री अरूण कुमार ने बताया कि आज पटना हवाई अड्डे से हर साल लगभग 15 लाख यात्रियों का आवागमन हो रहा है। भविष्य में 35–45 लाख यात्रियों के आवागमन की संभावना को देखते हुए आगामी तीन–साढ़े तीन वर्षों में नये टर्मिनल भवन के विकास की उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्णिया, दरभंगा, पटना एवं गया आदि राज्य के हवाई अड्डों को 'रिजनल कनेक्टिविटी स्कीम' के तहत वायुयान परिचालन– कम्पनियों की अभिरूचि के हिसाबन विकसित किया जा सकता है।

बैठक में संबंधित सरकारी विभागों और राज्यपाल सचिवालय के अधिकारी भी उपस्थित थे।

....